

## अध्याय-5: निष्कर्ष और सिफारिशें

### 5.1 निष्कर्ष

**5.1.1** आरआईएनएल ने अक्टूबर 2008 में चरण-I और अक्टूबर 2009 में चरण-II की समापन की परिकल्पित तारीख के साथ शून्य तारीख अर्थात 28 अक्टूबर 2005 से ₹ 8,692 करोड़ की लागत पर 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तक क्षमता विस्तारण शुरू किया। तत्पश्चात, आरआईएनएल को भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2010 में नवरत्न स्थिति के साथ प्रदत्त किया गया था। तदनुसार, जुलाई 2011 में आरआईएनएल के निदेशक मंडल (बीओडी) ने ₹ 12,291 करोड़ की राशि पर क्षमता विस्तारण के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन किया था। चरण-I और चरण-II की समापन तारीखों को भी अक्टूबर 2011 और अक्टूबर 2012 में संशोधित किया गया था। हालांकि, आरआईएनएल ने क्षमता विस्तारण के समापन की तारीखों को प्राप्त नहीं किया है और उसमें संशोधन जारी रखा था। चरण-II यूनितों में निर्माण कार्य अब भी चल रहा है (अगस्त 2014 को)। इस प्रकार, लम्बे समय और अधिवहित लागत के बावजूद क्षमता विस्तारण को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

**5.1.2** आरम्भ में आरआईएनएल ने आइआरआर को 14.02 प्रतिशत पर अनुमानित किया था। तथापि, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर एमओएस अब सहमत है कि आइआरआर में मूल रूप से प्रक्षेपित 14.02 प्रतिशत के प्रति 12.96 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी। यह दर्शाता है कि परियोजना व्यवहार्यता का निर्धारण आरआईएनएल / एमओएस द्वारा सम्पूर्ण रूप से नहीं किया गया था जिसके आधार पर विस्तारण प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना था। इस प्रकार, परियोजना रिपोर्ट में संगणित आइआरआर, नकद प्रवाह और पीएटी वास्तविक और प्राप्य नहीं था।

**5.1.3** सलाहकार की नियुक्ति ने अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं किया है क्योंकि सलाहकार को परियोजना की संकल्पना से क्षमता विस्तारण के कार्यान्वयन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), तैयार करने की बजाय सलाहकार ने केवल एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको आरआईएनएल द्वारा एमओएस को प्रस्तुत किया गया था जिसने डीपीआर के लिए आग्रह किए बिना आरआईएनएल को क्षमता विस्तारण के अनुमोदन की सूचना दी थी। इसके अलावा, सलाहकार द्वारा तैयार किए गए अद्यतित लागत अनुमानों में (-) 47 प्रतिशत से (-) 122 प्रतिशत की भिन्नता थी। आरआईएनएल ने पात्रता मानदण्ड, तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों, निविदाओं के विभिन्न चरणों को अंतिम रूप देने पर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार को कोई समय सीमा नहीं दी है जिसने अन्ततः परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब को बढ़ावा दिया।

**5.1.4** कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति रखने के मद्देनजर आरआईएनएल ने इस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ईआईएल) जिसके पास ओडिशा में लौह अयस्क और मैंगनीज खदानों के लिए छह लाइसेंस थे, में ₹ 361 करोड़ मूल्य के 51 प्रतिशत शेयर प्राप्त किए (जनवरी 2011)। हालांकि, आरआईएनएल इस निवेश से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सका और सभी छह लाइसेंस समाप्त हो चुके थे। राज्य सरकार द्वारा किसी भी लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया था (मार्च 2014)। आरआईएनएल के पास लौह अयस्क और कोकिंग कोयला के लिए अपने स्वयं के केप्टिव खदान नहीं है और इसलिए पश्च क्षमता विस्तारण से आरआईएनएल को कच्चे माल के प्रति उच्चतर लागत ने भुगतान के जोखिम की संभावना है।

**5.1.5** 3 एमटीपीए चरण में आरआईएनएल अपर्याप्त रोलिंग मिल्स पर कार्य कर रही थी और परिष्कृत इस्पात की बजाय सेमी-इस्पात की बिक्री पर न्यूनतम लाभ का अर्जन कर रही थी। आरआईएनएल ने मौजूदा क्षमता विस्तारण में रोलिंग मिल्स की पर्याप्त मेचिंग क्षमता की स्थापना के लिए योजना नहीं बनाई है। इसके अलावा, आरआईएनएल ने एसएलटीएम के कार्य को छोड़ दिया है (जनवरी 2014)। इस प्रकार, परियोजना नियोजन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह क्षमता में वृद्धि की सीमा तक रोलिंग मिल्स की मेचिंग क्षमता के प्रतिष्ठापन पर ध्यान नहीं देता जिससे कि उच्चतर राजस्व के अर्जन के लिए सेमी इस्पात को परिष्कृत उत्पाद में बदला जा सके।

**5.1.6** विनिर्देशों को देने, एनआईटी के निर्गम, पीक्यूसी खोलने, तकनीकी वाणिज्यिक बोलियों और स्वीकृति पत्र जारी करने में काफी विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप क्षमता विस्तारण के पूर्व कार्यान्वयन और कार्यान्वयन प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। ठेकों को अंतिम रूप देने के लिए आंतरिक समय सीमा का अभाव और निविदा शर्तों के निरूपण में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप अधिक समय लगा। आरआईएनएल ने ठेकों का प्रबंधन कुशलता से नहीं किया है और ऐसे विलम्बों को बढ़ाने वाले कारकों की जांच किए बिना ठेकेदारों को विस्तारण दिया है।

**5.1.7** बीओडी के निदेशों (फरवरी 2006) के बावजूद इसकी जानकारी हेतु प्रत्येक बोर्ड बैठक में क्षमता विस्तारण के संबंध में की गई प्रगतियों (प्रत्यक्ष और वित्तीय दोनों) की सूचना देने के लिए न तो आरआईएनएल ने निर्णय के अनुपालन का आश्वासन दिया और न ही बीओडी ने अपने स्वयं के निदेशों के अनुपालन हेतु जोर दिया। इस प्रकार, आरआईएनएल/बीओडी द्वारा परियोजना मॉनीटरिंग तंत्र त्रुटिपूर्ण था।

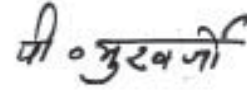
**5.1.8** आरआईएनएल ने 2010-11 तक क्षमता विस्तारण को शुरू करने के लिए वर्ष 2008-09 के लिए एमओएस के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में वचनबद्धता की थी। हालांकि, आरआईएनएल ने एमओयू लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका था, फिर भी इसने संशोधित प्रवर्तन तारीखों के साथ वर्ष 2009-10, 2011-12 और 2012-13 के लिए एमओयू में समान वचनबद्धता करना जारी रखा। इस प्रकार, एमओएस और आरआईएनएल के बीच किए गए एमओयूज ने क्षमता विस्तारण की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य नहीं किया।

## 5.2 सिफारिशें

हम निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं:-

1. आरआईएनएल इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार के साथ ओडिशा में खनन लाइसेंस के नवीनीकरण न होने का मामला उठाये जोकि उपयुक्त एजेंसियों के साथ मुद्दे को उठाये।
2. आरआईएनएल समापन की संशोधित निर्धारित तिथियों के अनुरूप क्षमता विस्तार का कार्य पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।
3. आरआईएनएल क्षमता विस्तार की परियोजना के शीघ्र निपटान में सलाहकार की संबद्धता के साथ उनकी भूमिका और प्राप्त किए गए मूल्य संवर्धन की सूक्ष्म समीक्षा करे।
4. आरआईएनएल परियोजना निष्पादन में नियंत्रणयोग्य देरी को कम करने और सुपुर्दगी की समयविधितय करने तथा निदेशक मंडल के स्तर पर निगरानी के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करे।
5. इस्पात मंत्रालय / आरआईएनएल सुनिश्चित करे कि क्षमता विस्तार से संबंधित कार्य के वास्तविक निष्पादन और एमओयू लक्ष्य के बीच एक सत्यापन योग्य कड़ी हो।

उपरोक्त सिफारिशों के संबंध में एमओएस ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आरआईएनएल ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों को स्वीकार किया और उनके यथावत अनुपालन के लिए सभी प्रयास करेगा।



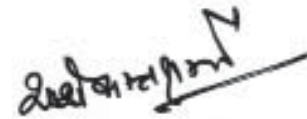
(प्रसेनजीत मुखर्जी)

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं  
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक : 20 मार्च 2015

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 21 मार्च 2015